निर्देश: खरीदारी के 14 दिनों के भीतर शुगर मिल्स किसानों को पेमेंट करें

'गन्ना किसानों के पेमेंट के मामले में सख्ती बरतें राज्य'

[ईटी ब्यूरो | नई दिल्ली]

गन्ना पेराई सीजन की शुरुआत होने के बाद खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि शुगर मिल्स चलने लगी हैं और उन्हें उम्मीद है कि राज्य सरकारें किसानों को गन्ना का भुगतान कराए जाने के मामले में सख्ती बरतेगी।

पासवान ने कहा कि इस साल 350 चीन मिलें काम कर रही हैं जबकि पिछले साल पेराई सत्र में 510 मिलें काम कर रही थीं। उत्तर प्रदेश की करीब 115 मिलों में से 90 में चीनी बनाने का काम शुरू हो चुका है।

पासवान ने कहा, 'जल्द ही मिलें काम करना शुरू कर देंगी।' उन्होंने कहा कि चीनी मिलों को गन्ना की खरीदारी किए जाने के 14 दिनों के भीतर किसानों को पेमेंट करने के लिए कहा गया है। पासवान ने कहा, 'राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि गन्ना किसानों को समय पर उनका पेमेंट मिले।' उन्होंने कहा कि चीनी मिलों पर फिलहाल किसानों का 3,640 करोड़ रुपये का बकाया है, जबकि 1 दिसंबर 2013 से लेकर अब तक चीनी मिलों पर 58,269 करोड़ रुपये की देनदारी है। उत्तर प्रदेश में चीनी मिलें अक्टूबर माह में किसानों को 3,055 करोड़ रुपये में से महज 1157 करोड़ रुपये का भुगतान कर पाई हैं जबकि कर्नाटक में अक्टूबर महीने में किसानों को 1,802 करोड़ रुपये बकाया में से 1,725 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। चीनी मिलों पर गन्ना किसानों के बकाया रकम की जानकारी देते हुए रामविलास पासवान ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बजाज ग्रुप, मोदी, मवाना और सिंभावली जैसी बड़ी चीनी मिलों को अभी किसानों को पिछली बार का भी पेमेंट देना है। उत्तर प्रदेश के चीनी मिलें राज्य सरकार की तरफ से तय किए गए अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य का हवाला देकर पेमेंट करने से बचते रही हैं। उन्होंने सरकार से गन्ने और चीनी की कीमत को जोड़ने के लिए कहा है जैसा कि महाराष्ट्र और कर्नाटक में किया गया है। महाराष्ट्र और कर्नाटक में चीनी की कीमतों के अनुपात में गन्ना किसानों को गन्ने का भुगतान किया जाता है। किसानों के हितों को सुरक्षित करते हुए हरियाणा सरकार ने 2014-15 पेराई सत्र के लिए गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर 305 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। उत्तर प्रदेश में एसएपी 280 रुपये प्रति क्विंटल है जिसमें से प्रति क्विंटल 40 रुपये की मदद केंद्र सरकार देगी। 1 अक्टूबर को चीनी का स्टॉक 72 लाख टन रहा है जबकि पिछले साल समान अवधि में यह 91 लाख टन था। शुगर इंडस्ट्री को लगता है कि 14 दिनों के भीतर गन्ना किसानों के एरियर का भुगतान करने में उन्हें परेशानी होगी क्योंकि फिलहाल देश में चीनी की कीमत प्रॉडक्शन लागत से कम है।

शुगर इंडस्ट्री परेशान

- **चीनी मिलों** पर किसानों का 3,640 करोड़ रुपये का बकाया है
- **जबकि 1** दिसंबर 2013 से लेकर अब तक चीनी मिलों पर 58,269 करोड़ रुपये की देनदारी है
- **उत्तर प्रदेश** में बजाज ग्रुप, मोदी, मवाना और सिंभावली चीनी मिलों को अभी किसानों को पिछली बार का भी पेमेंट देना है
- **शुगर इंडस्ट्री** का मानना है कि 14 दिनों के भीतर किसानों को एरियर देने में उन्हें परेशानी होगी

Economic times
11/12/14